



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 2001/30 अग्रहायण, 1923

---

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 21 दिसम्बर, 2001

संख्या 1-81/2001-वि० स०.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1975 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

(2001 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर.स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,  
सचिव ।

2001 का विधेयक संख्यांक 23.

## हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 14 दिसम्बर, 2001 को प्रवृत्त होगा और प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(1994 का 12) 2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के परन्तुक में, "3500" अंकों के स्थान पर "3000" अंक रखे जाएंगे। धारा 6 का संशोधन।

3. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का 1) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। 2001 के अध्यादेश संख्या 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।



## अद्वैत और कर्णों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 11 में वर्तमान कानूनों के अनुसार, पार्सों के निर्माण के प्रयोजन के लिए, पार्सों की जनसंख्या 3500 से कम नहीं होगी। नगर निगम के पार्सों के परिशीलन की प्रक्रिया, इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता से कनिष्ठ क्षेत्रों को प्रभावित करने के कारण, प्रारम्भ हो गई है और निर्माण कार्यक्रम के अनुसार पार्सों के परिशीलन से सम्बन्धित अधिनियम तारीख 14-12-2001 को जारी की जाती अपेक्षित थी। क्योंकि 2001 की जनगणना के दौरान अधिनियमित किए गए जनसंख्या के अधिकारे अभी तक प्रकाशित नहीं किए जा सके हैं। इसलिए, 1994 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए परिशीलन किया जाता है। वर्तमान नगर निगम में पार्सों की संख्या 25 है और हाथ ही में हमारे बाहर निकालने गए क्षेत्रों को आवंटित करने के कारण निगम की जनसंख्या 82 होगा होगी। अतः हम जान को भी सम्भावना है कि कुछ ऐसे पार्सों हो सकते हैं जिसकी जनसंख्या 3500 से भी कम हो। यह हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 11 से सम्बन्धित होगा। इसलिए, ऐसी अवस्था को दूर करने के लिए तुरन्त पद उठाए जाने अनिवार्य और आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, पार्सों की संख्या 3500 की न्यूनतम वर्तमान सीमा के स्थान पर 3000 की न्यूनतम सीमा का अन्वेषण करने हेतु उपर्युक्त अध्यादेश जारी करके पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक और अनिवार्य था।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मत में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का अध्यादेश संख्यांक 1) को 11 दिसम्बर, 2001 को प्रकाशित किया था और उसे तारीख 14 दिसम्बर, 2001 के राजपत्र (समाधारण) में प्रकाशित किया गया। अतः उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह निधेयक, उक्त अध्यादेश को, किसी उपान्तरण के बिना, प्रतिस्थापित करने के लिए है।

कम द्वारा कथन,  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख . . . . . 2001.

बिस्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-



**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

**Bill No. 23 of 2001,**

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION  
(SECOND AMENDMENT) BILL, 2001**

**(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)**

**A  
BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994).*

Enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows:

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2001.

Short title  
and com-  
mencement

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 14th day of December, 2001.

12 of 1994

2. In section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in clause (a), in sub-clause (ii), in the proviso, for the figure "3500", the figure "3000" shall be substituted.

Amend-  
ment of  
section 6.

1 of 2001

3. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed.

Repeal of  
Ordinance  
No. 1 of  
2001 and  
savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.



## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the provisions contained in section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the population of each ward shall not be less than 3500 for the purposes of elections of Councillors. The process of delimitation of ward for the Municipal Corporation, after excluding certain areas from its territorial jurisdiction, has begun and the notification regarding delimitation of ward was required to be issued on 14-12-2001 as per election programme. Since the population figure ascertained during the 2001 census has not yet been published, the delimitation has to be done after taking the 1991 census figure into account. The number of wards in the present Corporation is 25 and the population of the Corporation, after excluding the areas recently taken out would be 82,000 in the vicinity. It is thus likely that some of the wards may contain a population which may be less than 3500. This would be inconsistent with section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994. Therefore, it was necessary and urgent to take immediate steps to obviate an illegality. For this purpose it was imperative to amend the aforesaid Act by issuing an Ordinance so as to provide for the minimum population of 3000 as against the present minimum population of 3500 for each ward.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) had to be amended urgently, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated, under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2001 (Ordinance No. 1 of 2001) on the 14th day of December, 2001 and the same was published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 14th day of December, 2001. Now, the said Ordinance is required to be replaced by regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without modification.

ROOP DASS KASHYAP,  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA :  
The.....2001.

## FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-